www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 292 | जौनपुर शनिवार, 13 जून 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

हसन प्रीत को मेयर चुने जाने पर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी बधाई

बरनाला (पंजाब), (एजेंसी)। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सर्वसम्मति से बरनाला के पहले मेयर चुने जाने पर हसन प्रीत को बधाई दी। हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को कहा कि हसन प्रीत युवा, ऊर्जावान और उत्साही नेता हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्हें बरनाला के पहले मेयर के रूप में चुना गया है। वह विकास के कार्यों को गति देने का काम करेंगे। पहले बरनाला काउंसिल होता था, लेकिन अब यह नगर निगम के रूप में तब्दील हो चुका है। इसी वजह से हसन प्रीत को सर्वसम्मति से मेयर के रूप में चुना गया है। हाउस में कुल 50 सदस्य हैं, जिसमें से 49 सदस्यों ने हसन प्रीत के नाम पर मुहर लगाई। उन्होंने आगे कहा कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आम आदमी पार्टी के पक्ष में नतीजे आए। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों में इस नतीजे की वजह से धरातल पर स्थिति सकारात्मक होती हुई दिखेगी और विकास के कार्यों को भी बल मिलेगा। हमें इस बात की खुशी है। इसके अलावा, उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरनाक बन चुकी है। भाजपा लोकतंत्र के हितों पर लगातार प्रहार कर रही है। राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भाजपा मौजूदा राजनीतिक स्थिति को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है।

गुजरात से भाजपा के उम्मीदवार सभी चार राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध जीते

गांधीनगर, (एजेंसी)। गुजरात से राज्यसभा की सभी चार सीटों के लिए गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। नामांकन वापस लेने की समय सीमा खत्म होने तक कोई अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में नहीं था, जिससे इस महीने के आखिर में खाली होने वाली उच्च सदन की चारों सीटें भर गईं।भारतीय राजनीति समाचार रिटर्निंग ऑफिसर और गुजरात विधानसभा के सचिव चेतन पांड्या ने बिना किसी मुकाबले के द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद जितेंद्र कंजारिया, मानसिंह परमार, राजेश शुक्ला और मुकेश राठवा को राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किया।भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जून को राज्य में राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की थी। 8 जून तक नामांकन पत्र स्वीकार किए गए, और चार उम्मीदवारों ने वैध नामांकन दाखिल किए। 9 जून को कागजों की जांच पूरी हुई, और चारों नामांकन सही पाए गए। किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया, और उम्मीदवारों की संख्या खाली सीटों की संख्या के बराबर थी, इसलिए राज्यसभा चुनाव के नियमों के तहत यह चुनाव निर्विरोध हो गया।नए चुने गए सदस्य राज्यसभा के निवर्तमान सांसदों राम मोकारिया, नरहरि अमीन, रमीलाबेन बारा और शक्तिसिंह गोहिल की जगह लेंगे।

महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, आवास, खेल, विज्ञान और शासन जैसे क्षेत्रों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के सभी प्रयास गरिमा, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन पहलों ने ऐसा वातावरण तैयार करने में मदद की है, जहां महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें और राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी योगदान दे सकें। उन्होंने का उल्लेख करते हुए महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। नरेंद्र मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नए अवसरों के द्वार खोल रही है और देश के विकास परिदृश्य को नई दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रही है। उन्होंने बताया कि ये समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पीएम मोदी ने संस्कृत का एक सुभाषित साझा करते हुए कहा कि भारत की नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां अपनी प्रतिभा, परिश्रम और कौशल से हर क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। उन्होंने संस्कृत श्लोक उद्धृत किया "नारी त्रैलोक्यजननी नारी त्रैलोक्यरूपिणी। नारी त्रिभुवनाधारा नारी शक्तिस्वरूपिणीः" प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका अर्थ है कि स्त्री तीनों लोकों की जननी, उनकी अभिव्यक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार और शक्ति का वास्तविक स्वरूप है।

भारत के विकास के लिए चुनौतियों का किया सामना : सीएम नायडू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में गठबंधन सरकार ने पिछले दो वर्षों में युवजन श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार द्वारा छोड़ी गई चुनौतियों और संकटों से पार पाते हुए कल्याण, विकास और सुशासन सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) की सरकार के दो साल पूरे होने पर अपने विचार 'एक्स' पर साझा किए। उन्होंने कहा, "आज इस जन–सरकार के सत्ता संभालने के पूरे दो साल हो गए हैं, जिसे पांच करोड़ लोगों का भारी भरोसा हासिल है। पिछली सरकार चुनौतियों, संकटों और अनसुलझे मुद्दों की विरासत छोड़ गई थी, लेकिन हमने उन सभी से पार पाते हुए कल्याण, विकास और सुशासन सुनिश्चित किया है।" मुख्यमंत्री ने कहा, "हम इस विश्वास के साथ काम करते हैं कि सत्ता एक जिम्मेदारी है और शासन में बैठे लोग असल में जनता के सेवक होते हैं। हमारा एजेंडा हर नागरिक, हर परिवार और समाज के हर वर्ग की सफलता और भलाई पर केंद्रित है, उनकी उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करके हम राज्य के भविष्य का रास्ता बना रहे हैं।" टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। सीएम नायडू ने कहा, "सरकार के दो साल पूरे होने पर मैं राज्य के विकास के हर कदम पर अटूट समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं।

पीएम मोदी ने देश को पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार के दौर से बाहर निकाला : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को पॉलिसी पैरालिसिस और भ्रष्टाचार से बाहर निकाला। 2014 के पहले भारत आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। योजनाएं भ्रष्टाचार के कारण दम तोड़ देती थीं पर अब भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में बदल चुका है। मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही देश को आत्मविश्वास का एहसास हुआ। यही कारण है कि देश की सेनाएं अब दुश्मनों के घर में घुसकर वार कर रही हैं। दुनिया भारत की धमक को महसूस कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके लिए प्रदेश की जनता की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये कामना करता हूं कि उनका नेतृत्व देश को निरंतर मिलता रहे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोगों की आस्था को सम्मान देने का काम किया है। पीएम मोदी राम मंदिर के शिलान्यास, लोकार्पण और ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। ऐसा करके देश की आस्था को सम्मानित किया। वहीं, आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और जब राष्ट्रपति ने शामिल होने की कोशिश की तो उन्हें रोकने का प्रयास किया। सीएम योगी ने कहा कि ये पीएम मोदी की नेतृत्वक्षमता का ही प्रभाव है कि जब भी उन्होंने देश से आह्वान किया पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। कोरोना की त्रासदी में पीएम मोदी के आह्वान पर एक साथ खड़ा हुआ। इसी तरह जब आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ ।

कोलकाता में सुवेंदु ने गिनाईं भाजपा सरकार की उपलब्धियां, पश्चिम बंगाल को मिला बड़ा लाभ

कोलकाता, (एजेंसी)। सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में डबल–इंजन सरकार के लाभों पर जोर देते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, जनगणना जैसे रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने और जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत व पीएम सूर्य घर जैसी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का विस्तृत ब्यौरा दिया। इन उपलब्धियों में 54 लाख किसानों को पीएम किसान निधि और 40 लाख घरों का निर्माण शामिल है, जो राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं। पश्चिम बंगाल के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को डबल–इंजन गवर्नेंस मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से राज्य के लोगों को मिले फायदों पर जोर दिया। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, अधिकारी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में लागू की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से काम करेंगेय इतने कम समय में भी हमने कुछ काम पूरे कर लिए हैं। जनता को 'डबल–इंजन' सरकार के फायदे दिखने लगे हैं और आने वाले दिनों में ये फायदे और भी साफ तौर पर दिखाई देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अधिकारी ने कहा कि हमने को जमीन सौंप दी है। यह प्रक्रिया रोज चल रही हैय अब तक हमने लगभग 100 किलोमीटर तक की जमीन सौंप दी है। उत्तर बंगाल में, खासकर शचिकन्स नेकश कॉरिडोर से सटे इलाकों में, ने बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। जैसा कि आपने देखा है, हम इसे तय समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आखिरकार, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उन्होंने राज्य में पहले से रुके हुए कामों, जैसे कि जनगणना की प्रक्रिया, को लागू करने का भी जिक्र किया।

सीएम रेवंत रेड्डी ने छह महानगरों में से प्रत्येक को एक लाख करोड़ रुपए की मांग की

हैदराबाद, (एजेंसी)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में देश के छह प्रमुख महानगरों के विकास को लेकर बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु को वैश्विक स्तर के शहरों में बदलने के लिए प्रत्येक शहर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाए और इसके लिए एक विशेष श्एम–6 सिटीज टास्क फोर्सश का गठन किया जाए।नई दिल्ली में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये छह महानगर भारत की अर्थव्यवस्था के असली इंजन हैं। देश की लगभग 10 प्रतिशत आबादी इन शहरों में रहती है, और ये शहर भारत के कुल जीडीपी का करीब एक–चौथाई हिस्सा पैदा करते हैं। इसके बावजूद ये शहर अभी दुनिया के प्रमुख महानगरों के मुकाबले पीछे हैं।भारतीय राजनीति समाचार मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शहरों का विकास खर्च नहीं, बल्कि निवेश है, क्योंकि यही शहर देश के लिए राजस्व, रोजगार और वैश्विक पहचान पैदा करते हैं। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि इन महानगरों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने के लिए एक सशक्त राष्ट्रीय टास्क फोर्स बनाई जाए।रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भी केंद्र का सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अगले विकास चरण के लिए रीजनल रिंग रोड बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उद्योग, लॉजिस्टिक्स और नियोजित आवासीय विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने भारत फ्यूचर सिटी को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम (बंदर) डीप–वॉटर पोर्ट से जोड़ने के लिए 12–लेन एक्सप्रेसवे की मांग भी रखी। इसके अलावा, उन्होंने हैदराबाद मेट्रो रेल फेज–2 को मंजूरी देने, मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना के लिए सहायता और 30 हजार एकड़ में विकसित किए जा रहे श्नेट–जीरो ग्रीनफील्ड भारत फ्यूचर सिटीश के लिए वित्तीय सहयोग देने की मांग की।मुख्यमंत्री ने एस. जयपाल रेड्डी पलामुरु–रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी देने की भी अपील की।

ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का संदेश, छोटे किसानों को मजबूत किए बिना खाद्य सुरक्षा संभव नही

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और स्वच्छता के प्रतीक इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की कृषि शक्ति, सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक सहयोग की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में "वसुधैव कुटुंबकम" की भावना को आगे बढ़ाते हुए दुनिया को एक परिवार मानकर शांति, समन्वय और साझेदारी आधारित विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में "अतिथि देवो भवः" की भारतीय परंपरा का उल्लेख करते हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा वैश्विक एकता, शांति और सहयोग का समर्थक रहा है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण "युद्ध नहीं, शांतिय संघर्ष नहीं, समन्वय" पर आधारित है, जो वैश्विक कृषि सहयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह मंच विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के सामने मौजूद चुनौतियों, जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव और बाजार की अनिश्चितताओं का सामूहिक समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि छोटे किसान मजबूत होंगे तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा स्वतः सुदृढ़ होगी। शिवराज सिंह चौहान ने भारत की कृषि उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि पिछले एक दशक में कृषि क्षेत्र में औसतन 4.5ः वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि देश का कुल खाद्य उत्पादन बढ़कर लगभग 376 मिलियन टन तक पहुंच गया है। गेहूं उत्पादन करीब 118 मिलियन टन, बागवानी उत्पादन 378 मिलियन टन से अधिक और मत्स्य उत्पादन 19 मिलियन टन से ऊपर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संचालित करता है, जिसके माध्यम से बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

असम के मुख्यमंत्री सरमा ने बाल श्रम को खत्म करने के लिए किया सामूहिक प्रयासों का आह्वान

असम, (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' पर बाल श्रम को समाप्त करने और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा व विकास के अवसर सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "हमारे समाज का भविष्य हमारे बच्चों के हाथों में है। 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' पर, आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि उन हाथों में किताबें हों, बोझ नहीं और हर बच्चे को सीखने व आगे बढ़ने का अवसर मिले।" विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रम में लगे लाखों बच्चों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में बच्चों के शोषण को समाप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों का लंबे समय से यह मानना घ्हरहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा के उपाय और श्रम कानूनों का सख्ती से पालन बाल श्रम से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर विभिन्न सरकारी पहलों में स्कूल में दाखिले को बेहतर बनाने, स्कूल छोड़ने वालों की दर को कम करने और कमजोर परिवारों की मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। असम ने भी शिक्षा तक पहुंच और बच्चों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। मुख्यमंत्री का यह संदेश ऐसे समय में आया है जब बाल कल्याण से जुड़े समूह बाल श्रम को रोकने और बच्चों को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए अधिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की मांग कर रहे हैं।

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने पर दिया जोर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक के दौरान ह्यूमन कैपिटल (मानव पूंजी) को मजबूत करने पर हुई चर्चाओं का जिक्र किया। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर पोस्ट कर कहा, श्प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में शामिल हुआ। ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने और भारत की विकास यात्रा को तेज करने पर सार्थक चर्चा हुई, जिससे विकसित भारत 2047 के विजन को हासिल करने के हमारे साझा संकल्प को बल मिला।मोदी सरकार के 12 साल पूर्ण होने पर एक अन्य एक्स पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दशक में किसानों के कल्याण के लिए एनडीए द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ष्हमारे अन्नदाता, किसान भाई–बहनों की कड़ी मेहनत और समर्पण से ही देश की समृद्धि का रास्ता बनता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण को नई गति मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, पीएम–किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड और आधुनिक कृषि सुविधाओं जैसी पहलों ने किसानों को आत्मनिर्भर और मजबूत बनने में सक्षम बनाया है। किसानों का सम्मान करना, उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना और बेहतर भविष्य सुरक्षित करना प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में चल रही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे पहले सप्ताह में शिक्षा मंत्रालय ने तीन विश्व–प्रसिद्ध विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को मंजूरी पत्र जारी किए। धर्मेंद्र प्रधान ने इस घटनाक्रम को नेप 2020 के अंतरराष्ट्रीयकरण के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया।उन्होंने कहा कि भारत में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स द्वारा कैंपस स्थापित करने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैश्विक शिक्षण साझेदारी और अनुसंधान सहयोग को और मजबूती मिलेगी।

संपादकीय

आय एवं व्यय के आंकड़े

आय कर रिटर्न्स से उभरा रुझान साफ है। भारत में प्रत्यक्ष कर राजस्व अधिक से अधिक धनी वर्गों पर निर्भर होता जा रहा है। वैसे, विषमता बढ़ने की पुष्टि हवाई यात्रा संबंधी ताजा आंकड़ों से भी हुई है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए दाखिल हुए आयकर रिटर्न्स से देश में बढ़ रही आर्थिक गैर–बराबरी की झलक मिली है। एक अंग्रेजी वित्तीय अखबार के विश्लेषण के मुताबिक पांच लाख रुपये तक आमदनी वाले व्यक्तियों के रिटर्न की संख्या 2024–25 की तुलना में गिर कर लगभग आधी रह गई है। ऐसा संभवतरू इसलिए हुआ कि गुजरे वित्त वर्ष में सरकार के आय कर दरों में बढ़ोतरी करने की वजह से बहुत से लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने की अनिवार्यता नहीं रह गई। मगर इससे यह भी जाहिर होता है कि लोगों के क्रमिक रूप से ऊपर के आय वर्ग में शामिल होने का क्रम टूटा हुआ है। 2019–20 के बाद से 2022–25 तक पांच लाख से कम आबादी वाले वर्ग की ओर से सबसे ज्यादा रिटर्न फाइल होते थे। मगर अब पांच से दस लाख रुपये के बीच की आमदनी वाले समूह ने यह स्थान हासिल कर लिया है। 2024–25 में इस आय वर्ग में चार करोड़ 75 लाख रिटर्न फाइल हुए थे, जो पिछले वर्ष पांच करोड़ 45 लाख तक पहुंच गए। रुझान साफ है। भारत में प्रत्यक्ष कर राजस्व अधिक से अधिक धनी वर्गों पर निर्भर होता जा रहा है। वैसे, विषमता बढ़ने की पुष्टि हवाई यात्रा संबंधी ताजा आंकड़ों से भी हुई है। 2011–12 में हर दस लाख आबादी पर 649 परिवारों के 775 लोगों ने हवाई यात्रा की थी। तब कुल छह करोड़ 80 लाख हवाई यात्राएं हुईं। 2023–24 में हवाई यात्राओं की संख्या 15 करोड़ 37 लाख तक पहुंच गई। लेकिन ये यात्राएं हर दस लाख आबादी में 471 लोगों ने की, जो 469 परिवारों से आए। मतलब यह कि 2011 में हवाई यात्राओं की संख्या भले कम थी, मगर आबादी के हिसाब से यात्रियों का अनुपात कहीं बड़ा था। महंगी कारों एवं अन्य उपभोक्ता चीजों की खरीदारी के आंकड़ों से भी इसी रुझान का संकेत मिलता है। इसीलिए सरकार के विषमता घटने के दावों पर यकीन करना मुश्किल होता गया है। मसलन, पारिवारिक उपभोग खर्च सर्वे रिपोर्ट– 2023–24 में ऐसा दावा किया गया। जबकि आय एवं व्यय के अन्य आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं।

गृहिणियां राष्ट्र निर्माता हैं, उनके कार्यगत योगदान को कदापि कम मत आंकिए

कमलेश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गृहिणियों के योगदान पर एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि गृहिणियां राष्ट्र निर्माता हैं और उनके घरेलू व देखभाल संबंधी कार्यों का वास्तविक आर्थिक मूल्य है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रमुख टिप्पणियों में कहा कि गृहिणी को केवल आश्रित मानना गलत हैय वास्तव में पूरा परिवार उनके श्रम और देखभाल पर निर्भर रहता है। लिहाजा, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य भारत की ळक्च में अनुमानतः 15–17ः तक योगदान देता है, फिर भी उसे पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती। वह गृहणियां ही हैं जो बच्चों के पालन–पोषण, शिक्षा, संस्कार और मानव संसाधन निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती हैं। इसलिए अदालत ने कहा कि घरेलू कार्य को आर्थिक विश्लेषण से बाहर रखना उचित नहीं है और कानून को गृहिणियों के श्रम, सेवा और त्याग का मूल्य स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष यह कि गृहिणियां राष्ट्र निर्माता हैं, इसलिए उनके कार्यगत योगदान को कम मत आंकिए। देखा जाए तो एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में गृहिणी के घरेलू योगदान का मूल्यांकन करते हुए कम–से–कम ध्30,000 प्रतिमाह का मानक निधारित किया है तथा ष्सवे वि कवउमेजपब बंतमष् को अलग क्षतिपूर्ति मद के रूप में मान्यता दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि, ष्गृहिणी का घर में किया गया कार्य उसके कार्यालय जाने वाले पति के काम से कम मूल्यवान नहीं है। इसलिए न्यायपालिका का दृष्टिकोण अब स्पष्ट रूप से यह है कि गृहिणियां केवल परिवार की देखभाल करने वाली नहीं, बल्कि आर्थिक योगदानकर्ता और राष्ट्र निर्माता हैं। चुनौती अब यह है कि सरकारें, निजी संस्थान और समाज इस न्यायिक मान्यता को सामाजिक और आर्थिक नीतियों में कितना उतारते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि गृहिणियों का योगदान भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन विडंबना यह है कि उनके श्रम को अक्सर ष्कामष् के बजाय ष्कर्तव्यष् मान लिया जाता है। इसी कारण उनके योगदान को वह संस्थागत मान्यता नहीं मिल पाती जिसकी वे हकदार हैं। सवाल है कि गृहिणियों का आर्थिक योगदान कितना बड़ा है? तो अर्थशास्त्रियों और विभिन्न अध्ययनों के अनुसार यदि घर के भीतर किए जाने वाले कार्यकृजैसे भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा, घरेलू प्रबंधन, भावनात्मक देखभाल आदिकृका बाजार मूल्य जोड़ा जाए, तो इसका योगदान ळक्च के 15ः से 40ः तक आंका गया है। भारत में कई अध्ययनों ने इसे लगभग 15–17ः या उससे भी अधिक बताया है। पहला, जीडीपी की गणना का तरीकारू ळक्च केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को गिनता है जिनका बाजार में लेन–देन होता है। गृहिणी का श्रम घर के भीतर होता है, इसलिए वह राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में सीधी नहीं दिखता। दूसरा, ऐतिहासिक सामाजिक दृष्टिकोणरू सदियों से घरेलू कार्यों को महिलाओं का ष्स्वाभाविक दायित्वष् माना गया। जब किसी कार्य को कर्तव्य मान लिया जाता है, तो उसका आर्थिक मूल्यांकन कम हो जाता है। तीसरा, श्रम का अदृश्य होनारू एक गृहिणी दिनभर में दर्जनों काम करती है, लेकिन वे छोटे–छोटे हिस्सों में बंटे होते हैं। इसलिए उनका श्रम उतना दिखाई नहीं देता जितना किसी कार्यालय या फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति का। चौथा, नीति निर्माण में कम प्रतिनिधित्वरू सत्ता और नीति–निर्माण संस्थानों में लंबे समय तक पुरुषों का वर्चस्व रहा। परिणामस्वरूप घरेलू श्रम के आर्थिक मूल्यांकन का प्रश्न प्राथमिकता नहीं बन पाया। पांचवां, वेतन और मूल्य का भ्रमरू समाज अक्सर मानता है कि जिस काम के बदले वेतन नहीं मिलता, उसका आर्थिक मूल्य भी नहीं है। जबकि गृहिणी का श्रम परिवार की आय और उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। पहला, घरेलू श्रम का नियमित आर्थिक मूल्यांकन। दूसरा, जनगणना और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में गृहिणी श्रम का अलग लेखा–जोखा। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और बीमा योजनाओं का विस्तार। चौथा, घरेलू कार्यों को ष्अनपेड वर्कष् के रूप में नीति दस्तावेजों में मान्यता। और पांचवां, परिवारों में घरेलू जिम्मेदारियों का अधिक समान वितरण। गृहिणी केवल घर नहीं संभालती, वह भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करती है। एक शिक्षक, डॉक्टर, सैनिक, वैज्ञानिक, उद्यमी या नेता बनने से पहले हर व्यक्ति किसी परिवार में पलता–बढ़ता है। उस प्रक्रिया में गृहिणियों का योगदान आधारशिला जैसा होता है। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गृहिणियां केवल परिवार निर्माता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता भी हैं। चुनौती यह है कि समाज और संस्थाएं इस योगदान को भावनात्मक सम्मान के साथ–साथ आर्थिक और नीतिगत मान्यता भी दें। नारी तुम केवल श्रद्धा होष कृ नामक कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध पंक्ति भारतीय समाज में स्त्री

के सम्मान का आदर्श प्रस्तुत करती है। लेकिन आज यह प्रश्न स्वाभाविक है कि केवल श्रद्धा, सम्मान और प्रशंसा के शब्दों से कब तक काम चलेगा? यदि एक ओर स्त्री को ष्देवीष, ष्शक्तिष, ष्मांष और ष्राष्ट्र निर्माताष कहा जाए, और दूसरी ओर उसके श्रम, अधिकारों और योगदान को उचित मान्यता न मिले, तो यह विरोधाभास ही माना जाएगा। गृहिणियों के संदर्भ में यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है। यदि वे परिवार की आधारशिला हैं, बच्चों के माध्यम से भविष्य के नागरिकों का निर्माण करती हैं, उनका अवैतनिक श्रम अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है, और सर्वोच्च न्यायालय भी उन्हें ष्राष्ट्र निर्माताष मानता है, तो फिर केवल काव्यात्मक सम्मान पर्याप्त नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है कि सम्मान के साथ आर्थिक मान्यता की, प्रशंसा के साथ सामाजिक सुरक्षा की, आदर्शवाद के साथ नीतिगत बदलावों की, और प्रतीकात्मक गौरव के साथ व्यावहारिक अधिकारों की। इसी भावना को आधुनिक संदर्भ में यूँ कहा जा सकता है– नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह कहना अब पर्याप्त नहीं, तुम श्रम हो, सृजन हो, सामर्थ्य हो, तुम्हारा मूल्यांकन भी आवश्यक है। सम्मान के शब्द मधुर हैं, पर न्याय उससे भी अधिक आवश्यक है। दरअसल, 21वीं सदी की स्त्री–विमर्श का एक बड़ा संदेश यही है कि स्त्री को केवल पूजने या महिमामंडित करने के बजाय उसके योगदान को वास्तविक अवसर, अधिकार और मान्यता दी जाए। तभी ष्नारी तुम केवल श्रद्धा होष जैसी पंक्तियां अपने पूर्ण अर्थ में सार्थक होंगी।

असम-नगालैंड के बीच दशकों का विवाद खत्म, तेल समझौता संपन्न

नीरज

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिली है। केंद्र, असम और नगालैंड के बीच तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण को लेकर हुआ त्रिपक्षीय समझौता भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अभियान का निर्णायक अध्याय है। दशकों से विवाद और अस्थिरता में फंसे असम, नगालैंड सीमा क्षेत्र में तेल खोज का रास्ता खोलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन को नई ताकत दे दी है, जिसका लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटाकर भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाना है। यही वजह है कि अमित शाह ने इसे विकसित पूर्वोत्तर और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। हम आपको बता दें कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम–नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सहित केंद्र, असम एवं नगालैंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए साफ कहा कि इस समझौते ने विकसित पूर्वोत्तर के रास्ते में खड़ी अंतिम बड़ी बाधा हटा दी है। हम आपको बता दें कि असम और नगालैंड की सीमा से लगे विवादित क्षेत्र में तीन दशक से अधिक समय से तेल और खनिज अन्वेषण ठप पड़ा था। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव बना रहता था, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपये की संपदा जमीन के नीचे दबी रह गई। अब इस समझौते के तहत एक हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में तेल, गैस और खनिज संसाधनों की खोज और उत्पादन का रास्ता खुल गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राज्यों ने संसाधनों के बंटवारे पर 50–50 की सहमति बनाई है। यही वह राजनीतिक परिपक्वता है जिसने इस समझौते को टकराव से निकालकर साझेदारी के मॉडल में बदल दिया। अमित शाह ने दावा किया कि इस एक समझौते से प्रतिदिन एक हजार से पंद्रह सौ बैरल तेल उत्पादन क्षमता को दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है। केवल एक तेल क्षेत्र से पंद्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक की संभावित प्राप्ति का अनुमान जताया गया है। यह बयान केवल आर्थिक संभावना का संकेत नहीं, बल्कि उस रणनीतिक दिशा का संकेत है जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। वैश्विक भू–राजनीतिक तनाव, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति संकटों के दौर में भारत लंबे समय से आयातित तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में पूर्वोत्तर के विशाल तेल और गैस भंडार भारत के लिए नई ऊर्जा रीढ़ साबित हो सकते हैं। दरअसल यह समझौता केवल तेल निकालने का मसला नहीं है। यह पूर्वोत्तर को संघर्ष की पहचान से निकालकर सामरिक और आर्थिक शक्ति केंद्र में बदलने की कवायद है। अमित शाह ने कहा कि यदि नगालैंड में फैले तेल और गैस भंडार का पूरा दोहन हुआ तो भारत विदेशी देशों पर अपनी ऊर्जा निर्भरता काफी हद तक कम कर सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने ऊर्जा हितों को लेकर अधिक स्वतंत्र रणनीति अपना सकेगा। देखा जाये तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक मुद्दा नहीं होती, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल तत्व बन चुकी है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा बड़ा पहलू सुरक्षा और शांति से जुड़ा है। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में हिंसा की घटनाओं में लगभग अस्सी प्रतिशत गिरावट का दावा करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के बाद 12 शांति समझौते हुए हैं। यही कारण है कि अब सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को भी पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों से हटाने की तैयारी चल रही है। अमित शाह ने विश्वास जताया कि अगले वर्ष एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से यह कानून हटाया जा सकता है। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दशकों तक पूर्वोत्तर की पहचान उग्रवाद, सैन्य उपस्थिति और अस्थिरता से जुड़ी रही है। अब केंद्र सरकार यह संदेश देना चाहती है कि क्षेत्र संघर्ष से विकास की ओर बढ़ चुका है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह समझौता चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ी भारत की व्यापक नीति से भी मेल खाता है। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक केवल भौगोलिक सीमा माना जाता रहा, लेकिन अब उसे आर्थिक गलियारे, ऊर्जा केंद्र और संपर्क सेतु के रूप में विकसित किया जा रहा है। सड़क, रेल, निवेश, पर्यटन और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए केंद्र सरकार इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है। तेल और गैस परियोजनाओं के सक्रिय होने से निजी निवेश बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे और क्षेत्रीय असंतोष कम होगा। यही वह बिंदु है जहां विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी कहा कि यह समझौता देश की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। वहीं नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की सहमति इस बात का संकेत है कि अब पूर्वोत्तर की राजनीति टकराव से अधिक आर्थिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि अमित शाह ने इसे जीत हार का नहीं, बल्कि सबकी जीत का समझौता बताया। बहरहाल, अब स्पष्ट है कि यह त्रिपक्षीय समझौता केवल सीमाई विवाद सुलझाने का प्रयास नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने की शुरुआत है। यदि सरकार अपने दावों के अनुरूप तेल उत्पादन, निवेश और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा शक्ति, सामरिक मजबूती और आर्थिक विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

भारत की सेवा में विज्ञान के 12 वर्ष

डॉ. जितेंद्र सिंह

जब जम्मू के डोडा जिले की एक लैवेंडर किसान मौसम के पहले फूल तोड़ती है, तब वह विज्ञान नीति के बारे में नहीं सोचती। लेकिन सच यह है कि केंद्र शासित प्रदेश की बंजर पहाड़ियों को बैंगनी फूलों की सुगंधित खेती में बदलने के पीछे पिछले एक दशक में किया गया उद्देश्यपूर्ण और दूरदर्शी वैज्ञानिक निवेश ही है। यह ग्रामीण आजीविका में आई ऐसी क्रांति है, जिसकी शुरुआत एक प्रयोगशाला से हुई थी। असल में, भारत में पिछले बारह वर्षों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता का यही अर्थ है। विज्ञान केवल ज्ञान बढ़ाने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि वह हमारे नागरिकों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली एक जीवंत और प्रभावशाली शक्ति बन गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पदभार संभाला, तब उन्होंने एक ऐसी सोच प्रस्तुत की जिसमें विज्ञान को केवल किसी विभाग का काम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मिशन माना गया। इसके बाद के वर्षों में इस दृष्टि ने ऐसे परिणाम दिए, जो एक पीढ़ी पहले असाधारण माने जाते। आज भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतार चुका है, पहली बार अपनी स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित कर चुका है, पुणे से पटना तक सुपरकंप्यूटर स्थापित कर चुका है और एक ऐसे अंतरिक्ष अर्थतंत्र का निर्माण कर चुका है जिसमें देशी स्टार्टअप्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन उपलब्धियों की असली कहानी यह नहीं है कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि यह है कि इन उपलब्धियों ने आम नागरिकों के जीवन को किस तरह प्रभावित किया। विज्ञान अब केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय विकास और नागरिक सशक्तिकरण का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। किसानों का उदाहरण लें। भारतीय कृषि में मौसम हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पिछले एक दशक में पृथ्वी अवलोकन (अर्थ ऑब्जर्वेशन) और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप आज किसानों को सटीक और स्थानीय स्तर पर मौसम की जानकारी मिल रही है। यह केवल संभावनाओं पर आधारित अनुमान नहीं, बल्कि इतनी सटीक जानकारी है कि कोई किसान परिवार यह तय कर सकता है कि फसल आज काटनी है या कल तक इंतजार करना है। आज यदि बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात बनता है, तो हमारी आधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियां तटीय समुदायों को कई घंटे, और कई बार कई दिन पहले ही सचेत कर देती हैं। इसका महत्व केवल आंकड़ों में नहीं मापा जा सकताय इसका वास्तविक मूल्य उन अनगिनत जानों और आजीविकाओं में दिखाई देता है जो समय रहते बचाई जा रही हैं। जम्मू–कश्मीर की पहाड़ियों और नदी घाटियों में विज्ञान ने अरोमा मिशन के रूप में दस्तक दी। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को लैवेंडर की खेती से जोड़ा गया तथा उन्हें तकनीक, बेहतर बीज और बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराई गई। जो पहल एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी, वह आज भारत की पर्पल रिवोल्यूशन (बैंगनी क्रांति) के रूप में जानी जाती है। इसके माध्यम से हजारों किसान परिवार सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती से सम्मानजनक आय अर्जित कर रहे हैं। इस समृद्धि के पीछे विज्ञान ने एक शांत लेकिन निर्णायक भूमिका निभाई है। इसी प्रकार के प्रयासों के तहत केसर की खेती का विस्तार, औषधीय जड़ी–बूटियों का उत्पादन और भारत में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई। इन पहलों ने साबित किया है कि यदि नवाचार जमीन से जुड़ा हो, तो वह किसी भी औद्योगिक तकनीक जितना परिवर्तनकारी हो सकता है। विज्ञान के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण केवल कृषि तक सीमित नहीं रहा है। किफायती ग्रामीण आवास के लिए विकसित 3डी–प्रिंटेड घरों के मॉडल से लेकर खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों तक, तकनीक को उन समस्याओं के समाधान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका सामना समाज के सबसे कमजोर वर्ग करते हैं। कंप्यूटिंग, सेंसर तकनीक और इंजीनियरिंग को एक साथ जोड़ने वाले राष्ट्रीय अंतरूविषय साइबर–फिजिकल सिस्टम मिशन के तहत देशभर में 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों ने एक हजार से अधिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, जो सटीक कृषि, स्वच्छ पेयजल उपलब्धता और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान पर काम कर रहे हैं। ⊬ यदि कोई क्षेत्र भारतीय विज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति को सबसे प्रभावशाली ढंग से दिखाता है, तो वह जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा का क्षेत्र है। दशकों तक भारत की फार्मास्युटिकल ताकत मुख्य रूप से विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) तक सीमित रही। हम उन दवाओं के जेनेरिक संस्करण बनाते थे, जिनकी खोज दूसरे देशों में होती थी। अब यह कहानी बदल रही है। दशकों में पहली बार भारत में खोजी गई स्वदेशी एंटीबायोटिक नैफिथ्रोमाइसिन का विकास केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की घोषणा भी है।

मोदी युग ने भारत को नए सिरे से परिभाषित किया

पीयूष गोयल

वर्ष 2014 के बाद से, भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी अर्थव्यवस्था कहीं अधिक मजबूत हुई है। बुनियादी ढांचा निश्चित रूप से बेहतर हुआ है। महिलाएं बेहद सशक्त हुई हैं। किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं और गरीब अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हुए हैं। इन तमाम बदलावों में एक ही बात साझा हैरू प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि और उनका नेतृत्व। भारत के लोगों ने उनके दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व का भरपूर समर्थन किया है और उन्हें देश का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला निर्वाचित प्रधानमंत्री बनाया है। बीते 10 जून को उन्होंने राष्ट्र की सेवा में 4,399 दिन पूरे किए और अपनी पहली चुनावी जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। देश के लोगों ने ऐसे समय में 2014 में मोदी सरकार को भारी बहुमत से सत्ता सौंपी, जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी और यूपीए सरकार के बदनाम कार्यकाल के दौरान नीतिगत गतिरोधा, भ्रष्टाचार, घोटालों एवं विवादों को लेकर जनता में निराशा लगातार बढ़ रही थी। संवेदनशील नेतृत्व – 2014 से देश निरंतर बदलाव की यात्रा पर है। मोदी सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की, 58 करोड़ जन धन बैंक खातों के जरिए वित्तीय समावेशन को संभव बनाया और 16 करोड़ घरों तक नल के पानी का कनेक्शन पहुंचाया। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, श्आयुष्मान भारतय के जरिए 12 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी मिल रही है। कई युवा भारतीयों के लिए यह कल्पना करना मुश्किल हो सकता है कि मोदीजी द्वारा – पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में – लाए गए बड़े बदलावों से पहले जीवन कितना चुनौतीपूर्ण था। उनके निर्णायक नेतृत्व और नेक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण ने देश को श्विकसित भारत 2047य मिशन की दिशा में आगे बढ़ाया है। इस मिशन में भारत की विरासत पर गर्व और विकास का एक महत्वाकांक्षी एजेंडा शामिल है। नारी शक्ति प्रधानमंत्री के लिए महिलाएं केवल सहायता की लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र–निर्माता हैं। सबसे पहले उनकी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दिया गयारू स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। इससे उनकी सुरक्षा और सम्मान में वृद्धि हुई। वहीं, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इससे महिलाओं को धुएं से भरी रसोई के खतरों से मुक्ति मिली। श्बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओय की पहल ने बेटियों की शिक्षा एवं उनके कल्याण के महत्व को और ठोस बनाया है। श्नारी शक्ति वंदन अधिनियमय के जरिए, प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए देश की विधायिकाओं में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की है।

किसानों का कल्याण किसानों का कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का एक मुख्य आधार रहा है। किसानों के योगदान को मान्यता देते हुए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान) के जरिए उन्हें सीधे आय संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत बांटे गए कुल 4.28 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि से लगभग 10 करोड़ किसान परिवारों को लाभ हुआ है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी काफी बढ़ोतरी की है, जो अब उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना है। साथ ही, किफायती दरों पर फसलों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराकर किसानों को वैश्विक स्तर पर उर्वरकों की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी से बचाया गया है। युवाओं के लिए अवसर युवा भारतीयों के लिए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से, श्मेक इन इंडियाय और श्स्टार्टअप इंडियाय जैसी प्रमुख पहलें शुरू की गई हैं। श्कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालयय के रूप में एक समर्पित मंत्रालय के गठन से जहां युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुकूल कौशल से लैस करने में मदद मिली है, वहीं भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के क्षेत्र में उभरती हुई क्रांति का लाभ उठाने के लिए तैयार भी किया गया है। श्स्टार्टअप इंडियाय और नवाचार को दिए गए व्यापक समर्थन ने कई युवाओं को नौकरी खोजने वाला से हटकर नौकरी देने वाला बनने में मदद की है। इन पहलों ने उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) की एक ऐसी नई लहर की नींव रखी है, जिसमें आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के मामले में अहम योगदान देने की क्षमता है। अर्थव्यवस्था और जीवनयापन में सुगमता वर्ष 2014 से पहले, भारत की गिनती दुनिया की ष्फ्रैजाइल फाइवष (कमजोर पांच) अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में होती थी। निवेशकों का भरोसा भी लगातार कम हो रहा था। साहसिक सुधारों, निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों, वित्तीय अनुशासन और अपेक्षाकृत कम महंगाई के सहारे, भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यह कारोबार व निवेश का एक आकर्षक स्थल बनता जा रहा है। भारत ने विभिन्न विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इससे हमारे युवाओं, किसानों, छोटे व्यवसायों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर नए अवसर खुले हैं। और ऐसा भारत के हितों से समझौता किए बिना किया गया है। यह यूपीए सरकार द्वारा किए गए

कुछ लापरवाही भरे समझौतों से बिल्कुल अलग है। सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और करों की कम दरों जैसे बड़े सुधारों के जरिए कारोबार जगत और मध्यम वर्ग का भरोसा भी बढ़ाया है। इंटरनेट की पैठ और डिजिटल भुगतान प्रणाली के तेज विस्तार के साथ मिलकर, श्डिजिटल इंडियाय पहल ने अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालने के साथ–साथ नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को भी आसान बनाया है। कई पुराने एवं मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने तथा अनुपालन के अनावश्यक बोझ को कम करने से कारोबार जगत को और भी अधिक लाभ हुआ है। मध्यम वर्ग को भी काफी राहत मिली है और 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय को आयकर से छूट दे दी गई है। आधुनिक बुनियादी ढांचा मोदी सरकार देश के बुनियादी ढांचे में तेजी से बदलाव ला रही है। सक्रिय हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। वर्ष 2014 में सक्रिय हवाई अड्डों की संख्या 74 थी और अब यह 160 से अधिक हो गई है। बड़े पैमाने पर रेलवे के विद्युतीकरण, महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने देश के कई हिस्सों के बुनियादी ढांचे को दुनिया के बेहतरीन बुनियादी ढांचों की बराबरी में ला खड़ा किया है। प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का वास्तविक महत्व कार्यकाल के दिनों की गिनती में नहीं, बल्कि किए गए व्यापक बदलावों में निहित है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने गरीबों एवं किसानों के कल्याण, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं और उभरते भारत की महत्वाकांक्षाओं को शासन के केन्द्र में रखा है। अब जबकि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है, 2047 तक श्विकसित भारतय के निर्माण के नए संकल्प के साथ बदलाव की यह यात्रा निरंतर जारी रहेगी।

जौनपुर नशे में धुत मुख्य आरक्षी का वीडियो वायरल, एसएसपी ने किया निलंबित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में सुजानगंज थाने में तैनात मुख्य आरक्षी रामधनी यादव का कथित रूप से शराब के नशे में धुत वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। बक्शा थाना क्षेत्र के कौली गांव में हुए चर्चित हत्या प्रकरण के बाद कानून–व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामधनी यादव की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह वर्दी में नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह भावुक होकर रोते–बिलखते नजर आ रहे हैं तथा अपने थाना प्रभारी के संबंध में टिप्पणी भी कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने पुलिस विभाग की कार्यशैली और अनुशासन पर सवाल उठाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं और जनता का विश्वास प्रभावित करती हैं। एसएसपी ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है। साथ ही पूरे प्रकरण की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विधान भवन में योग चेतना सेमिनार एवं सम्मान समारोह सम्पन्न

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। राज्य विधान मंडल पेंशनर संस्थान तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी स्थित विधान भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर योग चेतना विषय पर सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस पर शुभकामनाओं के साथ हुई तथा प्रधानमंत्री के सबसे अधिक कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री को भी संस्थान की ओर से बधाई दी गई। जिसमें देश भर से आए योग विशेषज्ञों, प्रतिष्ठित चिकित्सको ,सामाजिक कार्यकर्ताओं,स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं, वैलनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग तथा अधिवक्ताओं ने अपने–अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य विधानमंडल पेंशनर संस्थान के अध्यक्ष डॉ० सी०पी० शर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यू० पी०एग्रो के अध्यक्ष मा० जगदीश मिश्रा उर्फ बाल्टी बाबा ने कहा कि आज के व्यस्ततम समय में तथा भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन में योग एक अहम भूमिका निभाता है। तथा समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के राष्ट्रीय संगठन सचिव मा०संजय श्री हर्ष,पदम श्री डॉक्टर के०के० ठकराल,सहारनपुर से वी०पी० सिंह, पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, संयुक्त सचिव विधानसभा अजीत वर्मा, माननीय राजीव मिश्र क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवध क्षेत्र, जयपुर से राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग के अध्यक्ष गोविंद जांगिड़, अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गुप्ता, पूर्व विशेष सचिव विधानसभा डॉ०दिनेश चंद्र अवस्थी, डॉ० शिखा गुप्ता, रुखसाना नकवी सहित सैकड़ो लोग उपस्थित रहे। उपरोक्त कार्यक्रम का सफल संचालन डॉ० हरिप्रकाश अग्रवाल के द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम के पूर्व में श्रीमती चित्रा दीक्षित के सौजन्य से अन्नपूर्णा भंडारे का भी आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान प्रदान किया गया। सम्मानित होने वालों में मुख्य रूप से डॉ० अरुण कुमार भरारी को योग एवं वैलनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा सम्मान के साथ–साथ योग एवं नेचुरोपैथी, स्वच्छ पर्यावरण, सामाजिक एकता एवं मानव धर्म के माध्यम से मानवीय मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से सार्थक मोटर बाईक यात्राओं के लिए ट्रैवल टाईकून इंडिया अवार्ड 2026 प्रदान किया गया। राष्ट्र गौरव शर्मा को समाज क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा सम्मान, डॉ० रूपाली राठौर को न्याय तथा विधि के श्रेत्र में, डॉ० विनोद कुमार यादव को योग एवं वैलनेस के क्षेत्र में, रूपचंद साहू को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, योग गुरु कृष्ण दत्त मिश्र को योग के क्षेत्र में, डॉ०आसिफ अली को वैलनेस तथा होम केयर सर्विसेज के क्षेत्र मे,डॉ० विवेक शर्मा को स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्रमें, एवं सर्वेश कुमार सोनी, वान्या मिश्रा, मीना गौतम, मीना मल्होत्रा, रजनी मिश्रा, सुनील कुमार द्विवेदी, डॉ० पुष्पा यादव, डॉ० राकेश प्रताप सिंह, शोभा रानी एवं डॉ० शिखा गुप्ता को भी सम्मानित किया गया। तथा साथ में जयपुर से पधारे गोविंद जांगिड़ को उनके बाल विकास के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए मेडिटेक ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से युवा प्रेरणा अवार्ड प्रदान किया गया।

जौनपुर में आंधी-बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में पिछले एक सप्ताह से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शनिवार को तेज आंधी और हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। हालांकि मौसम में बार–बार हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है और सर्दी, जुकाम व बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा था। इस प्रकार अधिकतम तापमान में करीब एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार सुबह करीब 11:00 बजे तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया। बारिश के बाद वातावरण में ठंडक बढ़ी और लोगों को गर्मी से राहत महसूस हुई। पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और उमस के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था। सुबह 10 बजे के बाद ही सड़कों पर आवाजाही कम हो जाती थी और लोग घरों में रहने को मजबूर थे। गर्मी से राहत पाने के लिए शीतल पेय और ठंडे खाद्य पदार्थों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। उधर चिकित्सकों ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। शनिवार को अचानक मौसम में परिवर्तन को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है।

योग से जागता है ऊर्जा और आत्मविश्वास : कुलपति

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व आयोजित विशेष योग सत्र में शनिवार को कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह के नेतृत्व में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का इनडोर स्टेडियम सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन और उत्साह से सराबोर हो उठा। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने स्वयं योग प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के लगभग 600 छात्र–छात्राओं को योग, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया। इस अवसर पर कुलपति ने विभिन्न योगासनों एवं ध्यान की विधियों का प्रशिक्षण देते हुए योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और व्यक्तित्व विकास का सशक्त आधार है। योग व्यक्ति के तन, मन और आत्मा को जोड़कर जीवन को संतुलित, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। प्रो. वंदना सिंह ने कैडेटों से नियमित रूप से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान भागदौड़ भरे जीवन में योग तनाव को कम करने और कार्यक्षमता बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने बताया कि कई ऐसे सरल योगाभ्यास हैं जिन्हें अध्ययन या कार्यालय के दौरान बैठकर भी किया जा सकता है। उन्होंने भारतीय ऋषि–मुनियों और महापुरुषों के जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि योग के माध्यम से उन्होंने न केवल दीर्घायु प्राप्त की, बल्कि अद्भुत ऊर्जा, एकाग्रता और कार्यक्षमता का परिचय भी दिया। योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसे अपनाकर युवा पीढ़ी स्वस्थ एवं सशक्त राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेटों में विशेष उत्साह देखने को मिला। योगाभ्यास के बाद विद्यार्थियों ने इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन में अनुशासन, एकाग्रता और सकारात्मकता का वातावरण बना रहा, जिसने सभी प्रतिभागियों को योग के प्रति प्रेरित किया।

रेडक्रॉस और परी आपकी रसोई ने संयुक्त रूप से दिया सेवा और सहयोग का संदेश'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' ष्परी आपकी रसोईष् में जरूरतमंद एवं असहाय लोगों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराकर जनपद में ष्अन्नदाताष् के रूप में एक विशेष पहचान रखने वाले समाजसेवी एवं ष्परी आपकी रसोईष् के संचालक विनय अग्रवाल ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ विजय जौहरी के आवास पर पहुंचकर उनसे भेंट की। डॉ. विजय जौहरी ने उनका आत्मीय स्वागत करते हुए मानव सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि विनय अग्रवाल द्वारा ष्परी आपकी रसोईष् के माध्यम से गरीब, असहाय एवं मरीजों के तीमारदारों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत सराहनीय एवं प्रेरणादायक कार्य है। वर्तमान समय में यह सेवा वास्तव में मानवता की मिसाल है। मुलाकात के उपरांत विनय अग्रवाल ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के मानवीय सेवा सहायता कक्ष एवं राहत सामग्री भंडार का अवलोकन किया। उन्होंने रेडक्रॉस द्वारा संचालित आपदा राहत, रक्तदान, स्वास्थ्य सेवा, कंबल वितरण, वस्त्रदान तथा जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े विभिन्न सेवा कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर डॉ विजय जौहरी ने विनय अग्रवाल को पटका पहनाकर, स्मृति चिन्ह एवं रेडक्रॉस मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा में समर्पित व्यक्तित्वों का सम्मान करना रेडक्रॉस की गौरवशाली परंपरा है तथा ऐसे सेवाभावी लोगों से समाज को नई दिशा और प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि विनय अग्रवाल जैसे सेवाभावी व्यक्तित्वों का रेड क्रॉस परिवार से जुड़ाव संस्था के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे समाजसेवियों का उनके आवास पर आगमन इस बात का प्रतीक है कि समाज सेवा करने वाले लोग एक–दूसरे के कार्यों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस अवसर पर विनय अग्रवाल ने कहा कि इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी विश्व की सबसे प्राचीन एवं प्रतिष्ठित मानवतावादी संस्थाओं में से एक है। मानव सेवा, शांति एवं पीड़ित सहायता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रेडक्रॉस आंदोलन को चार बार नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह संस्था वर्षों से असहाय, रोगग्रस्त, आपदा पीड़ित एवं जरूरतमंद लोगों की सेवा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में डॉ विजय जौहरी के नेतृत्व में रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आपदा राहत, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, कंबल वितरण, व्हीलचेयर एवं सहायक उपकरण वितरण, वस्त्रदान, स्वच्छता सामग्री वितरण तथा जरूरतमंद रोगियों की सहायता जैसे अनेक सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने का जो प्रयास रेडक्रॉस द्वारा किया जा रहा है, वह अन्य संस्थाओं के लिए भी प्रेरणा का विषय है। उन्होंने जनपद के रेडक्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की भूरि–भूरि प्रशंसा की।

बजाज कंपनी के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी का खुलासा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में पुलिस ने बजाज कंपनी के नाम पर लोगों को झांसा देकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, फर्जी दस्तावेज, बैंक खाते से जुड़े अभिलेख और नकदी बरामद की है। शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक शहर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त शुभम सिंह (30) पुत्र अनिल सिंह, निवासी पपरावन थाना बरसठी, जौनपुर, बजाज कंपनी में लोन, निवेश, टूर एंड ट्रेवल्स तथा इंश्योरेंस पैकेज दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था। वह फर्जी वेबसाइटों और ऑनलाइन माध्यमों से ग्राहकों का संपर्क हासिल कर उन्हें फोन व व्हाट्सएप के जरिए विश्वास में लेता था। आरोपी पीड़ितों से दस्तावेज लेकर लोन और निवेश की प्रक्रिया का झांसा देता था तथा प्रोसेसिंग फीस, सत्यापन शुल्क, इंश्योरेंस, कैशबैक और लोन अप्रूवल शुल्क के नाम पर रकम वसूलता था। जांच में सामने आया कि उसने फर्जी पते पर कूटरचित आधार कार्ड तैयार कराए थे, जिनके जरिए फर्जी सिम कार्ड हासिल किए जाते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से तीन एंड्रॉइड मोबाइल, तीन की–पैड मोबाइल, चार सिम कार्ड, एक फर्जी आधार कार्ड, एक फर्जी आधार की छायाप्रति, एक असली आधार कार्ड, 15 एटीएम कार्ड, नौ बैंक पासबुक, सात चेकबुक तथा 1.45 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने अपने, परिजनों और परिचितों के नाम पर कई बैंक खाते खुलवाए थे। साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि इन्हीं खातों में मंगवाई जाती थी और बाद में एटीएम, चेकबुक तथा सीएससी केंद्रों के माध्यम से निकाल ली जाती थी। पुलिस के अनुसार गिरोह अब तक 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर धोखाधड़ी कर चुका है। मामले में आरोपी के भाई, बहन तथा बहनोई के खातों की भी जांच की जा रही है।

बदनाम करने वालों का तबादला करें : एके शर्मा

लखनऊ, (संवाददाता)। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और पॉवर कॉर्पोरेशन के बीच अंदरखाने चल रही अनबन बृहस्पतिवार को खुलकर सामने आ गई। ऊर्जा मंत्री ने पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष कुमार गोयल पर पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री ने कहा है कि गर्मी में कई विद्युत कर्मियों ने निष्ठापूर्वक कार्य किया है, लेकिन कुछ कर्मियों ने लापरवाही कर सरकार को बदनाम किया। ऐसे कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। वर्तमान ट्रांसफर सीजन में इनका यथायोग्य तबादला किया जाए। इस बारे में उन्हें भी जानकारी दें। पत्र में लिखा है कि मई में आंधी तूफान के कारण विद्युत अवसंरचना बुरी तरह प्रभावित हुई है। 30 मई की समीक्षा बैठक में पता चला कि ऐसी चुनौतीपूर्ण समय में आप मुख्यालय से बाहर हैं। आगे भी तीन दिन बाहर रहेंगे। आग्रह करने पर ऑनलाइन बैठक हुई। किसी भी उच्चअधिकारी का यह व्यवहार जनहित के विपरीत एवं गैरजिम्मेदाराना है। भविष्य में मुख्यालय छोड़ने से पहले मुझे अवगत कराया जाए। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ईंधन अधिभार शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। कहा, जब पॉवर कॉर्पोरेशन ऊर्जा मंत्री और नियामक आयोग का नहीं सुन रहा है तो किसकी सुनेगा? उन्होंने पूरे मामले में सीएम योगी से हस्तक्षेप करने और उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की मांग की है। वर्मा ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जून में 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क लगाना सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन है।

संक्षिप्त खबरें

औद्योगिक निवेश को मिला प्रोत्साहन, यीडा को 399.36 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) को 399.36 करोड़ रुपये की फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।यह स्वीकृति राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी गई है। स्वीकृत राशि दो प्रमुख औद्योगिक इकाइयों को आवंटित भूमि पर दी गई 75 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत एसेंट–के सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड को 55.28 करोड़ रुपये तथा अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड को 344.08 करोड़ रुपये की राशि अनुमन्य की गई है।औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2022 के लिए प्रावधानित निधि से उपलब्ध कराई जाएगी।सरकार का कहना है कि इस तरह की प्रोत्साहन योजनाओं से प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।

अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

लखनऊ, (संवाददाता)। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों के शिक्षा, सुरक्षा और समग्र विकास के अधिकारों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना है।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति प्रस्तावित है। इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मुन्नू लाल कोरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक भी सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय विभाग एम.के. शन्मुगा सुन्दरम तथा श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में लगभग 800 प्रतिभागियों के शामिल होने की संभावना है। श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य के प्रति जनसहभागिता को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही बाल श्रम निषेध से जुड़े कानूनी प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी।विभाग ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में सक्रिय सहयोग करें और किसी भी बच्चे को श्रम में संलग्न न होने देने के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। विभाग का कहना है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर भविष्य उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।

राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में राजस्व विभाग को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को एनेक्सी भवन में राजस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्यमंत्री (राजस्व) सुरेंद्र दिलेर ने की। इस दौरान विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।बैठक में भूमि संबंधी विवादों, चकबंदी कार्यों, भू–अध्याप्ति परियोजनाओं, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, लंबित प्रकरणों के निस्तारण तथा आमजन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए तथा लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए।सुरेंद्र दिलेर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राजस्व विभाग को तकनीक–सक्षम, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और सभी राजस्व सेवाएं निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध हों।बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों तथा लंबित मामलों की जानकारी प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान कार्यों में तेजी लाने, विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और जनसेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।बैठक में राजस्व परिषद, राहत आयुक्त कार्यालय, चकबंदी विभाग, भू–अध्याप्ति निदेशालय तथा अन्य संबंधित इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विद्युत सखी' योजना से बदली ग्रामीण महिलाओं की तस्वीर

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार की 'विद्युत सखी' योजना ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और अंकीय अभिशासन का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित इस योजना ने जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल संग्रहण व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया है, वहीं हजारों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है।योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 'विद्युत सखी' के रूप में प्रशिक्षित कर स्मार्टफोन और अन्य तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके माध्यम से वे उपभोक्ताओं के घर पहुंचकर बिजली बिलों का संग्रहण करती हैं और तत्काल रसीद उपलब्ध कराती हैं। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए दूर–दराज स्थित विद्युत उपकेंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।विद्युत सखियों को उनके द्वारा जमा कराए गए राजस्व के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। दो हजार रुपये तक के बिल पर 20 रुपये प्रति बिल तथा इससे अधिक राशि के बिलों पर कुल संग्रहित धनराशि का एक प्रतिशत लाभांश प्रदान किया जाता है।योजना की सफलता की मिसाल शामली जनपद के ऊन विकास खंड स्थित हसनपुर गांव की निवासी अनीता हैं। भारती महिला ग्राम संगठन के अंतर्गत संचालित 'सृष्टि स्वयं सहायता समूह' की सदस्य अनीता कभी सीमित आय और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थीं।

गोरखपुर में 29.63 लाख वोटर, 1273 पंचायतों में 4626 बूथों पर करेंगे मतदान, 900 वोटर प्रति बूथ

गोरखपुर, (संवाददाता)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद गांवों में सियासी तापमान चढ़ गया है। भले ही चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है लेकिन अब मतदाता सूची के आधार पर समीकरण बनने–बिगड़ने लगेंगे। बुधवार को मतदाता सूची जारी होने के बाद गांवों के चौपाल पर चाय की चुस्की के दौरान गांव की सरकार बनाने को लेकर चर्चाएं भी होने लगीं। जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद 29,63,142 मतदाता हो गए हैं। कुल 6,03,576 नाम बढ़े और डुप्लीकेट और विस्थापित हुए 5,64,149 मतदाताओं के नाम काटे गए। ऐसे में कुल 39,427 हजार ही मतदाताओं की वृद्धि हुई। 1273 ग्राम पंचायतों में 4626 बूथों पर मतदान होगा। सभी बूथों पर 900 मतदाता मतदान करेंगे। पहली बार सभी मतदाताओं को उनका अलग स्टेट वोटर नंबर दिया गया है, नौ अक्षर एवं अंक का है। पुनरीक्षण कार्य में लगे 1941 बीएलओ को मतदाता सूची दे दी गई है, उन्हें निर्देश दिया गया है कि गांवों में जाकर लोगों के बीच मतदाता सूची का वाचन करें। पहले दिन कई बूथों पर लोगों ने बीएलओ का इंतजार किया। जब बीएलओ पहुंचेंगे तो लोग अपने नाम देख सकेंगे। उधर, बुधवार को मतदाता सूची लेकर गांवों में बीएलओ बुधवार दोपहर बाद पहुंचे। कई गांवों में प्रशासक बने निवर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक भी जुट गए और ज्यादातर गांवों में जुड़े और कटे नामों को देखने के लिए उत्सुकता बढ़ गई। जिन गांवों में बीएलओ नहीं पहुंचे वहां के लोगों ने फोन करके संपर्क साधा। ग्राम प्रधानों और संभावित प्रत्याशियों के घरों पर देर शाम तक समर्थक पहुंचते रहे और चुनाव को लेकर चर्चाएं होती रहीं। बुधवार को दोपहर बाद से ही गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है। अभी मतदाता सूची को जांचने में लगे हैं। पहले तो हमें देखना है कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अगर समर्थकों का नाम ही नहीं रहेगा तो चुनाव का सारा समीकरण फेल हो जाएगारू राधेश्याम जायसवाल, ग्राम प्रधान, लहसड़ी अभी मतदाता सूची में देखेंगे कि समर्थकों का नाम तो नहीं कट गया है। शाम से ही बहुत सारे लोगों के फोन भी आए हैं कि उनका नाम तो नहीं कटा। मतदाता सूची से सारे समीकरण बनते–बिगड़ते हैं। इसलिए इसे जांचना बहुत जरूरी है अंतिम मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड हो जाएगी।

गोरखपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बनेगी सिक्सलेन सड़क, एयरपोर्ट की तर्ज पर एंट्री-एग्जिट

गोरखपुर, (संवाददाता)। रेलवे स्टेशन परिसर में मुख्य द्वार से आने–जाने के लिए सिक्सलेन सड़क बनेगी। इसकी चौड़ाई 30 मीटर होगी। इसमें दो लेन प्रवेश और निकास एवं तीसरा लेन फुटपाथ के लिए होगा। एयरपोर्ट की तरह ही जिस रास्ते यात्री प्रवेश करेंगे, उधर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जून के अंतिम सप्ताह में कार्य शुरू कराने की तैयारी है। सिक्सलेन सड़क निर्माण के लिए स्टेशन परिसर में स्थापित हेरिटेज रेल इंजन और कोच रेस्टोरेंट को हटाया जाएगा। रेल प्रशासन ने कोच रेस्टोरेंट का लाइसेंस निरस्त भी कर दिया है। इसके अलावा कार व बाइक पार्किंग भी तोड़ी जाएगी। इसी जगह पर सड़क बनाई जाएगी। वर्तमान सभी सात प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे और सिर्फ एक प्रवेश और एक निकास द्वार रहेगा। साथ ही एक इमरजेंसी द्वार भी बनाने की योजना है। रेल प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रस्ताव के मुताबिक, 12.5–12.5 मीटर दो लेन की सड़क होगी और पांच मीटर का फुटपाथ बनेगा। 15 जनवरी 1885 को सोनपुर से मनकापुर तक मीटर गेज रेल लाइन के निर्माण के साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन अस्तित्व में आया। वर्ष 1886 में गोरखपुर से उस्का बाजार लाइन के निर्माण के साथ ही गोरखपुर जंक्शन स्टेशन बना। स्टेशन पुनर्विकास योजना के तहत निर्माण कार्य के क्रम में 30 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए हेरिटेज रेल इंजन और कोच रेस्टोरेंट को 20 जून तक हटाने की तैयारी है

संक्षिप्त खबरें

आंधी के साथ हुई बूंदाबांदी, अधिकतम तापमान छह डिग्री गिरा

भदोही, (संवाददाता)। जिले में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बुधवार की रात रुक–रुक कर तीन बार बूंदाबांदी हुई। जिससे बृहस्पतिवार को हवाओं में नमी रही। अधिकतम तापमान में छह डिग्री और न्यूनतम पारा में दो डिग्री की कमी देखी गई। तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं जिला प्रशासन ने 13 जून तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। जिले में बीते दो दिनों से रात में बूंदाबांदी हो रही है। मंगलवार की रात हल्की बरसात हुई, इसी तरह बुधवार की रात एक बजे से साढ़े तीन बजे तक रुक–रुक तीन बार बारिश हुआ। हवा में नमी रही, उमस भरी गर्मी से बेचैन लोगों ने राहत की सांस ली। बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे तक हवाओं के बीच आसमान में बादलों की आवाजी लगी रही। इस दौरान तापमान लगातार 42 से 43 डिग्री के आसपास बना था। मौसम की तल्खी का असर था कि दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस दौरान बीच–बीच में मौसम में बदलाव भी देखा गया। हालांकि बुधवार की रात अचानक बदले मौसम के बाद बारिश और तेज हवाओं का असर बना रहा। जिससे तापमान में गिरावट भी देखने को मिली। चिकित्सकों के अनुसार यह मौसम सेहत के लिहाज से नुकसानदेह है। लापरवाही बरतने पर लोग बीमार पड़ सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां प्रभारी डॉ. अजीत चतुर्वेदी ने बताया कि दो दिनों से रात में बूंदाबांदी हुई है। इसके कारण अधिकतम पारा छह डिग्री कमी के साथ 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। वहीं न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की गिरावट आई। पारा 27 डिग्री रही।

उपभोक्ता आयोग ने महाविद्यालय की लापरवाही पर लगाया चार लाख हर्जाना

भदोही, (संवाददाता)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने श्रीदेवी प्रसाद महाविद्यालय पिलखिनी, जंघई को छात्र के विषय के अलावा अन्य चीजें गलत दर्ज करने पर दोषी ठहराया। आयोग ने महाविद्यालय को आदेश दिया कि वह एक छात्र को 4 लाख रुपये हर्जाना और 10 हजार रुपये वाद शुल्क दें। चेताया कि महाविद्यालय नियत समय पर भुगतान नहीं करता है, तो उसे 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि सराय कंसराय निवासी प्रांशु तिवारी ने 2025–26 सत्र में बीएससी (बायो) में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। महाविद्यालय ने उनके विषय को बायो के बजाय मैथ लिख दिया था। इसके अलावा, छात्र के पिता का नाम, मोबाइल नंबर और पता भी गलत दर्ज किया गया। गलत मोबाइल नंबर के कारण प्रांशु को परीक्षा की सूचना नहीं मिल सकी। जब सूचना मिली तो प्रवेश पत्र में मैथ विषय देखकर वह परीक्षा नहीं दे पाए। छात्र के पिता हरिकेश तिवारी ने प्रबंधक राजमणि यादव और प्राचार्या काव्या पांडेय से संपर्क किया। उन्हें त्रुटि सुधारने में कोई मदद नहीं मिली, जिससे प्रांशु की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा छूट गई। पीड़ित छात्र ने 25 मार्च 2026 को जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया। उसने महाविद्यालय से साढ़े चार लाख रुपये हर्जाना और 10 हजार रुपये वाद शुल्क की मांग की थी।

अब शादी–बर्थडे के लिए भी नगर निगम की परमिशन जरूरी

गोरखपुर, (संवाददाता)। महानगर में स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम जल्द ही केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2026 को लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए नगर निगम सदन की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद शादी, बहूभोज जैस बड़े आयोजनों के साथ–साथ जन्मदिन, सगाई, फेयरवेल, कॉलोनी समारोह और अन्य निजी कार्यक्रम भी नगर निगम की निगरानी के दायरे में आएंगे। बुधवार को आयोजित कार्यशाला में मेयर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, उपसभापति पवन त्रिपाठी, नगर आयुक्त अजय जैन और अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने पार्षदों को नए नियमों की जानकारी दी।

महेवा मंडी में मसाला जांच करने पहुंचीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी का व्यापारियों ने किया विरोध

गोरखपुर, (संवाददाता)। नवीन गल्ला मंडी महेवा में वृहस्पतिवार को मसालों की जांच के लिए पहुंचीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा उपाध्याय का व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध के चलते वह मसालों के नमूने नहीं ले सकीं और बिना जांच किए वापस लौट गईं। बाद में उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा को लिखित रिपोर्ट भेजकर इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, शासन के निर्देश पर प्रदेशभर में मसालों में मिलावट की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नवीन गल्ला मंडी महेवा से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जाने थे। जांच शुरू होते ही बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्र हो गए और विरोध जताने लगे। व्यापारियों का आरोप है कि अधिकारी निजी वाहन से अकेले मंडी पहुंचीं और नमूना लेने के नाम पर व्यापारियों में भय का माहौल बना रही थीं। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने अपने लाइसेंस और खरीद–बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी दिखाए, इसके बावजूद उन्हें परेशान किया गया। सूचना मिलने पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को शांत कराया। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर बृजेश बंसल, आनंद गुप्ता, पवन सिंघानिया, पंकज गुप्ता, मनोज गोयल, पवन गुप्ता, अमित गोयल, पुनीत अग्रवाल, रमेश कसौधन, संजय जायसवाल आदि व्यापारी मौजूद रहे। शासन के निर्देश पर मसाले में मिलावट का प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में जांच कर रहे हैं।

खजांची-पादरी बाजार मार्ग पर खुले हैं नाले, चलें तो जरा संभलकर- मौत के बाद भी लापरवाही

गोरखपुर, (संवाददाता)। खजांची चौराहे से पादरी बाजार जाने वाले मार्ग पर हरसेवकपुर नंबर–दो के राजनगर मोहल्ले के पास अधूरा नाला हादसों को दावत दे रहा है। इस जगह पर करीब 200 मीटर लंबाई में नाले पर स्लैब नहीं लगे हैं। नाला पूरी तरह से खुला है। यहां हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यहां पहले भी कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि एक दिन पहले ही इसी नाले में गिरकर एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। हादसे के बाद उस जगह को अस्थायी रूप से घेर दिया गया है। इसी जगह पर गोड़धोईया नाला निर्माण भी चल रहा है। आगे कुछ दूरी पर जाने पर सड़क से सटा यह नाला पूरी तरह खुला पड़ा है। कई स्थानों पर लोग मजबूरी में लकड़ी, पटरी का रास्ता बनाकर आते–जाते हैं। नाले के किनारे दुकानें भी हैं। एक निजी अस्पताल भी है जहां मरीजों और तीमारदारों का आना–जाना लगा रहता है। ऐसे में जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बाइक और साइकिल सवारों को हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए चलना और भी जोखिम भरा है। नाला तो बन गया लेकिन स्लैब न लगने और सुरक्षा इंतजाम न होने से लोगों की जान को खतरा है। सभी कार्यदायी संस्थाओं को बैरिकेडिंग कर काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। जहां भी नाले खुले हैं, उन्हें तत्काल ढका जाएगा। यदि लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

बाहरी आडंबरों के नहीं भाव के भूखे हैं भगवान : प्रज्ञा

वाराणसी, (संवाददाता)। नगर के रामलीला मैदान में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के अंतिम दिवस बृहस्पतिवार को कथा व्यास सुश्री प्रज्ञा ने भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता, रुक्मिणी विवाह और भक्ति की महिमा की कथा सुनाई। कथा व्यास ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि सच्ची मित्रता धन–दौलत नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित होती है। श्रीकृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा का जिस प्रकार सम्मान किया, वह मानवता और मित्रता का सर्वोच्च उदाहरण है। रुक्मिणी विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए प्रज्ञा ने बताया कि श्रीकृष्ण ने धर्म और प्रेम की रक्षा के लिए रुक्मिणी का हरण कर उनसे विवाह किया।

सड़क हादसे में युवक की मौत, तीन घायल

भदोही, (संवाददाता)।गोपीगंज कोतवाली के सुजातपुर खलिया निवासी गोपाल गौतम (48) की बुधवार की रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह बिहरोजपुर से पंकजपुर बरौत जा रही बरात में शामिल होने जा रहे थे। बरौत बाजार में अचानक सामने एक ट्रक ने इनके ट्रैक्टर में टक्कर मार दिया। जससे उनकी मौत हो गई। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोपीगंज कोतवाली के बिहरोजपुर गांव से बुधवार की रात एक बरात पंकजनगर बरौत जा रही थी। अधिकतर बराती पहले ही निकल गए थे। सुजातपुर खालिया गांव निवासी शिवपाल ने बताया कि उनके भाई गोपाल गौतम (48), सुरेंद्र (25) निवासी बिहरोजपुर, लेखपाल (20) निवासी गोपीगंज व डीएम (20) निवासी खालिया एक ट्रैक्टर पर सवार होकर बरात में शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बरौत ओवरब्रिज के पास बाजार में प्रवेश करने के लिए जैसे ही ट्रैक्टर मुड़ा। इस बीच विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर में टक्कर मार दिया। जिसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को नजदीकी चिकित्सालय में ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने गोपाल गौतम को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल सुरेन्द्र, लेखपाल व डीएम को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

पशु तस्करी के दोषी को एक साल की सजा

भदोही, (संवाददाता)। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दुर्गेश ने बृहस्पतिवार को पशु तस्करी के दोषी को एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। ऊंज पुलिस ने 2019 में एक ट्रक में भरकर ले जा रहे 20 बैल को बरामद किया था। पुलिस ने ट्रक चालक मुबारक हुसैन उर्फ मैसर निवासी फतेहपुर घाट, पूरामुफ्ती, कौशांबी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय दुर्गेश ने आरोपी मुबारक हुसैन उर्फ मैसर को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को एक साल की सश्रम कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

वाराणसी में हर महीने एक उम्रकैद, टंकी में शव छिपाने और हत्या में कठोर सजा

वाराणसी, (संवाददाता)। जघन्य अपराधों के मामलों में वाराणसी की अदालतों ने पिछले दो वर्षों के दौरान त्वरित सुनवाई कर दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। वर्ष 2024 से अब तक 25 मामलों में दोष सिद्ध होने पर सजा दी जा चुकी है। इनमें हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो और दुष्कर्म के प्रयास के बाद हत्या जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो औसतन हर महीने एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन मामलों में कुछ ऐसी घटनाएं भी रहीं, जिन्होंने समाज को झकझोर दिया। अदालत ने भी उन्हें अत्यंत जघन्य अपराध मानते हुए दोषियों के प्रति सख्त रुख अपनाया और कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए गंभीर खतरा हैं। रामनगर क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को बोरे में भरकर स्कूल के पीछे फेंक दिया गया था। इस मामले में अदालत ने महज 11 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर दोषी इरशाद को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसी तरह कैंट थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर शव को पानी की टंकी में छिपाने के मामले में आरोपी सनोज उर्फ राहुल को आजीवन कारावास की सजा दी गई। आरोपी ने बच्ची की गला दबाकर हत्या की थी। भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की सरेआम पीट–पीटकर हत्या के मामले में भी अदालत ने सख्त रुख अपनाया। सुनवाई के बाद 16 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। एक अन्य चर्चित मामले में पत्नी की हत्या कर शव को घर के आंगन में दफनाने वाले आरोपी पति को भी अदालत ने दंडित किया। जांच में सामने आया था कि हत्या के बाद आरोपी ने शव को जमीन में दबाकर उस पर नमक डाल दिया था, ताकि साक्ष्य नष्ट किए जा सकें। पिछले एक वर्ष में दुष्कर्म और पॉक्सो से जुड़े कई गंभीर मामलों पर अदालत ने विशेष चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्ष 2024 से अब तक सजा पाए 25 मामलों में बड़ी संख्या दुष्कर्म और पॉक्सो से संबंधित रही है। कई मामलों में दुष्कर्म के प्रयास में असफल होने पर पीड़ित की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने ऐसे अपराधों को अत्यंत क्रूर और अमानवीय बताते हुए कठोर दंड सुनाया। इन फैसलों से यह स्पष्ट संकेत गया है कि जघन्य अपराधों के मामलों में न्यायपालिका त्वरित सुनवाई और कड़ी सजा के जरिए अपराधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपना रही है।

पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या

प्रयागराज, (संवाददाता)। औद्योगिक थाना क्षेत्र के गोती गांव में पूर्व प्रधान के 19 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक घर के पीछे बाग में बैठा था। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसे गोल मार दी। गोली लगते ही युवक जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घरवाले उसे अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में नैनी के एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार औद्योगिक थाना क्षेत्र के गोती गांव निवासी पूर्व प्रधान विनोद कुमार सिंह के दो बेटों में छोटा बेटा कुश कुमार सिंह (19) गुरुवार दोपहर घर से 50 मीटर दूर बाग में बैठा था। इसी दौरान अपाचे बाइक से तीन लोग उसके पास पहुंचे। आरोपियों ने कुश कुमार को गोली मार दी। गोली लगते ही कुश कुमार जमीन पर गिर पड़ा और हमलावर मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो कुश कुमार खून से लथपथ पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कुश को तत्काल स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय भेजा। जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए नैनी के एक पूर्व प्रधान को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। गांव वालों ने बताया कि विनोद कुमार सिंह जब सपा में थे, तब प्रधानी का चुनाव जीता था। अब वह पूर्व प्रधान हैं और भाजपा में हैं। घटना के बारे में मृतक के बड़े भाई शिवम ने बताया कि कई वर्ष से मुकदमा चल रहा है। 8 बीघा जमीन का दीवानी मुकदमा लगा हुआ था। 2022 में सुरेश यादव के पक्ष से गोली चलाई गई थी।

एटीएम में फेवीक्विक लगाकर निकाल लिया 71 हजार रुपए

प्रयागराज, (संवाददाता)। कैंट थाना क्षेत्र में ठगों ने शातिराना तरीके से एक व्यक्ति के खाते से 71,050 रुपए निकाल लिए। तीन युवक पहले एटीएम केबिन में पहुंचे। एटीएम के कार्ड स्लॉट में फेविक्विक लगा दिया, जिससे उसमें कार्ड फंस जाए। कुछ देर बाद एक व्यक्ति रुपए निकालने एटीएम पहुंचा। जैसे ही उसने कार्ड डाला, वह मशीन में फंस गया। वह काफी देर तक परेशान होता रहा, तभी वहां पहले से मौजूद युवकों ने उसे एक हेल्पलाइन नंबर देकर कॉल करने को कहा। पीड़ित ने कॉल की। फोन पर मौजूद युवक ने खुद को बैंककर्मी बताया। उसने पीड़ित से पिन पूछ लिया। काफी कोशिश के बाद भी जब कार्ड नहीं निकला तो पीड़ित कार्ड छोड़कर चला गया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने प्लास की मदद से कार्ड निकाल लिया। आरोपियों ने पिन की मदद से कैश निकाला, शॉपिंग की और करीब 18 हजार रुपए की शराब पी डाली। कैंट थाना क्षेत्र के स्टैनली रोड निवासी मो. आसिफ खान ने बताया कि 31 मई की शाम करीब साढ़े सात बजे राजापुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में रुपए निकालने गए थे। एटीएम कक्ष में पहले से तीन अज्ञात युवक मौजूद थे।

कुक और सिक्योरिटी गार्ड बनने रूस गए थे अजहरुद्दीन और रामचंद्र, ताबूत में हुई वापसी

वाराणसी, (संवाददाता)। रूस में कुक और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने गए जिले के अजहरुद्दीन और रामचंद्र के कंकाल बृहस्पतिवार को उनके घर लाए गए। दोनों को रूस–यूक्रेन युद्ध में उतार दिया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच करीब तीन साल से युद्ध चल रहा है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर लड़े जा रहे इस युद्ध में आजमगढ़ जिले का नाम भी शामिल हो गया था। यहां के आठ लोग लापता हो गए थे। आजमगढ़ और मऊ जिले के कई लोग नौकरी की तलाश में जनवरी 2024 में एजेंटों के जाल में फंस कर रूस चले गए। इनमें से आजमगढ़ के कन्हैया यादव और मऊ के श्यामसुंदर और सुनील यादव की रूस–यूक्रेन जंग में मौत हो चुकी थी। आजमगढ़ के राकेश यादव और मऊ के बृजेश यादव घायल होने के बाद घर लौट आए थे। वहीं विनोद यादव, जोगेंद्र यादव, अरविंद यादव, रामचंद्र, अजहरुद्दीन खान, हुमेश्वर प्रसाद, दीपक, धीरेंद्र कुमार लापता हो गए थे। कंधरापुर थाना के खोजापुर माधवपट्टी निवासी योगेंद्र यादव भी उसी में थे। परिवार के लोगों का कहना था कि मऊ के एजेंट विनोद यादव ने सभी को फंसाया था। गार्ड की नौकरी के लिए लेकर गए और बार्डर पर भेज दिया। 15 जनवरी 2024 को विनोद, सुमित और दुष्यंत नामक एजेंट के साथ गए।

बंधवा बड़े हनुमान जी मंदिर पर युवक को पुलिसकर्मियों ने पीटा

प्रयागराज, (संवाददाता)। संगम क्षेत्र स्थित बड़े हनुमान मंदिर में पुलिस कर्मियों ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवक को घूंसों से जमकर पीटा। मारपीट का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद डीसीपी सिटी जोन ने जांच के आदेश दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवक अपनी बहन के साथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। बताया जा रहा है कि वे मंदिर परिसर में मौजूद महंत के दर्शन करने के लिए बैरिकेडिंग के आगे जाने का प्रयास कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोका। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में विवाद में बदल गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लगभग 9 सेकंड के वीडियो में कई पुलिसकर्मी एक युवक को घेरकर उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।